



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1156]
No. 1156]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 2008/श्रावण 21, 1930
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 2008/SAKANA 21, 1930

शहरी विकास मंशोधन

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2008

क्र.आ. 2034(अ).—यतः नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधारणों के अनुसार सार्वजनिक सूचनाओं के रूप में सं. क्र.आ. 1049(अ) दिनांक 30-4-2008, 1142(अ) दिनांक 15-5-2008, 1172(अ) दिनांक 19-5-2008, 1396(अ) दिनांक 9-6-2008 और 1397(अ) दिनांक 9-6-2008 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (2) द्वारा यथा-अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के बीतर आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में आपत्तियाँ/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जौच और सुनवाई बोर्ड तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भी विचार किया गया; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने भास्मे के सभी पहलुओं पर व्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 में अनुलग्नक 'क' तथा 'ख' के अनुसार निम्नलिखित संशोधन करती है।

[सं. के-12011/5/2007-डी डी आई बी]

पी. के. सातरा, अवर सचिव

अनुलग्नक-क्र

क्र. सं.	पृष्ठ सं०	दिल्ली भारटर प्लान-2021का पैरा/खंड सं०	संशोधन
1.	27	उप पैरा 4.4.3 के तहत शर्त (xvii)	<p>इस शर्त के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया:- (xvii) निम्नलिखित को छोड़कर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को नियमित नहीं किया जाएगा और उसे अतिरिक्त निर्माण अथवा ऊंचाई के नियमन हेतु स्थानीय निकाय की स्वीकृति से पूर्व हठा दिया जाएगा :-</p> <p>"(क) अनियोजित ब्लॉकों(विशेष क्षेत्र, गांव आबादी और अनधिकृत नियमित कालोनियों सहित) और पुनर्वास कालोनियों में 1982 से पूर्व की कालोनियों (के तथा ख श्रेणी को छोड़कर) में 24 भीटर मार्गाधिकार से कम की सड़कों पर 175 वर्ग मी० तक के प्लाटों के लिए भू-सतह से 3 भीटर की ऊंचाई से ऊपर 1 भीटर तक के 7.2.2007 से पूर्व मौजूद प्रोजेक्सन/छज्जा/कवर्ड छज्जा निर्भित भाग को नियमित किया जाएगा। भूस्वामियों/कब्जाधारकों को सरकार द्वारा यथा अधिसूचित यथोधित समयावधि में संरचना सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र और अग्रिम सुरक्षा संबंधी मंजूरी लेनी होगी। इस प्रकार के प्रोजेक्सन/निर्भित भाग को एफएआर में लिया जाएगा और अनुमत्य एफएआर से अधिक और अतिरिक्त एफएआर के मामले में ऐसे आधिक्य एफएआर को सरकार द्वारा यथा अनुशोदित प्रभार का भुगतान करने की शर्त पर नियमित किया जाएगा।</p> <p>(ख) अधिसूचना की तारीख के दो माह के भीतर संबंधित स्थानीय निकाय नियमितीकरण के लिए पात्र ऐसे सभी प्रोजेक्सनों के संबंध में एक सर्वेक्षण करेगा और इनकी सूची को सार्वजनिक रखेगा ताकि कब्जाधारक/ भूस्वामी और जनता का कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रोजेक्सनों को सूची में शामिल करने/शामिल न करने के संबंध में अपनी आपत्तियां रख सके और लिखित में प्राप्त ऐसी आपत्तियों पर विचार करके एक माह के भीतर सूची को अंतिम रूप देगा। "</p>
2.	35-36	सारणी 5.4 4(ग) होस्टल	(ग) होस्टल के बिकास नियंत्रण मानकों को अनुलग्नक-“ख” के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3.	46	सारणी 7.3 के नीचे नोट (v)	<p>इस नोट के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-</p> <p>"V. औद्योगिक परिसरों में बैंकवेट हॉल की अनुमति होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित परिवर्तन प्रभारी सहित निर्धारित किए जाने वाले विनिर्देशों/ विनियमों के अध्यधीन होगी। "</p>

4.	46	सारणी 7.3 के नीचे नोट (vi)	इस नोट के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा । "vi. औद्योगिक हकाइयों/प्लॉट जो 24 मी और उससे ऊपर के मार्गाधिकार वाली सड़कों के साथ संलग्न हैं, वे विद्यमान विकास नियंत्रण मानवों के अंतर्गत व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तन के लिए पात्र होंगी, बरते कि वे सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित परिवर्तन प्रभारों और पार्किंग की लागत का भुगतान कर देते हैं । ऐसे प्लाटों में स्थानीय बाजारों में अनुमेय कार्यकलापों की अनुमति होगी । इसके अतिरिक्त बहुस्तरीय पार्किंग की भी अनुमति होगी । तथापि, इसकी अनुमति असंगत/ नियमित लिए गए औद्योगिक ब्लॉकों में नहीं दी जाएगी । उपर्युक्त प्रावधान किसी भी प्रकार से उच्चतम न्यायालय के आदेशों को प्रभावित नहीं करेगा । "
5.	78	उप पैरा 12.12.2 के नीचे खंड (vii)	इस नोट के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा । "vii. अधिकातम 10 एकड़आर, सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित परिवर्तन प्रभारों/स्कूलों के भुगतान की शर्त पर अज्वलनशील, अहानिकारक व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए अनुमेय हैं ।"
6.	97	सारणी 13.21 के तहत क्रम सं0 14	इस क्रम सं0 में "स्वीकार्य कार्यकलाप" सीरिक के तहत इंडोर गेम्स हॉल के बाद "स्विमिंग पूल" जोड़ा जाएगा ।"
7.	97	सारणी 13.21	इस सारणी के नीचे निम्नलिखित नोट जोड़ा जाएगा । "नोट 1. इंडोर गेम्स हॉल में फिजिकल ट्रेनिंग और उपकरण स्वीकार्य कार्यकलाप है ।"
8.	113	उप पैरा 15.3.2(1) के तहत "अन्य कार्यकलाप" पर स्पष्टीकरण	इस स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:- "पैरा नं0 15.7 में दी गई शर्तों के अधीन जैसा कि पैरा 15.7.1 में परिचालित है, "अन्य कार्यकलाप" गेस्ट हाउस नर्सिंगहोम और प्री-प्राह्मणी स्कूलों तक सीमित है । ये उन प्लाटों में अनुमत होंगे, जो नियमित प्लॉटिड विकास में क्रम से क्रम 18 मी0 मार्गाधिकार वाली सड़कों से लगते होंगे, क्योंकि यह कार्यकलाप "सार्वजनिक और अर्थ-सार्वजनिक सुविधाओं" के रूप में है । नए बैंक, फिटनेस केन्द्रों, वेलनेस केन्द्रों और गैर-सरकारी संगठनों को अनुमति नहीं दी जाएगी । लेकिन जो बैंक 7.9.2006 को पहले से ही विद्यमान है फिटनेस केन्द्र और वेलनेस केन्द्र तथा गैर-सरकारी संगठन जो 7.2.2007 को भौजूब हैं (जैसा कि पैरा 15.7.1 में दर्शाया गया है) समय-समय पर इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं के अनुसार हैं और अधिसूचना की सिद्धि को क्रम से क्रम 18 मी0 मार्गाधिकार की सड़कों से लगे हुए प्लाटों पर हैं, कार्य करते रहेंगे ।"
9.	114	उप पैरा 15.3.2(सभी श्रेणी की कालोनियों में शुप हाउसिंग) के	इसके स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:- "केवल व्यावसायिक कार्यकलाप और पैरा 15.6.3 के अनुसार छोटी दुकानें अनुमत्य होंगी और स्कूल के बच्चों के लिए ट्यूशन केन्द्रों को अनुमति दी जाएगी । समूह आवास के ले-आउट प्लान में विशेष रूप

		नीचे स्पष्टीकरण(4)	से उपलब्ध कराई गई फुटकर दुकानें तथा पैरा 5.4(ii) के तहत समूह आवास में अनुमत्य गतिविधियों की अनुमति होगी। ”
10.	115	उप पैरा 15.3.3 के तहत खण्ड(i)	इस खण्ड को संशोधित किया जायेगा और इसे निम्नवत पढ़ा जाए :- “(i) उस भाग/गली में जहां 50 प्रतिशत से अधिक प्लाटों में भू-तल पर स्थानीय झोंपिंज केन्द्र में अनुमत्य दुकानें/कार्यालय और अन्य गतिविधियां चल रही हैं, ऐसी गली/भाग को मिश्रित उपयोग सङ्क के रूप में अधिसूचित किया जा सकेगा। ”
11.	114	उप पैरा 15.3.3 के तहत खण्ड (iv)	इस खण्ड के बाद, निम्नलिखित नोट जोड़ा जायेगा: ‘नोट-1 स्थानीय निकाय इस अधिसूचना के तीन माह की अवधि के भीतर 7.2.2007 को अधिसूचित दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के प्रावधानों के अनुसरण में शहरी गांवों में सर्वेक्षण करेगा तथा सर्वेक्षण नहीं की गई अनधिकृत कालोनियों को नियमित करेगा। ”
12.	115	उप पैरा 15.4(ii) के तहत ग्रुप हाउसिंग में	“ केवल----- की अनुमति दी जाएगी” वाक्य के बाद निम्नलिखित जोड़ा जायेगा:- “तथापि, मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक उपयोग क्षेत्र/स्ट्रेच/सङ्कों पर डीडीए प्लैटों के समग्र भूतल पर निश्चित उपयोग/व्यावसायिक उपयोग की अनुमति है। दो अथवा अधिक डीडीए प्लैटों को मिलाने की अनुमति नहीं होगी। ”
13.	115	15.6	इस उप पैरा के जीर्ण को संशोधित किया जायेगा और इसे “फुटकर दुकानें और कार्यालय” के रूप में पढ़ा जाए।
14.	115	उप पैरा 15.6.1 के तहत खण्ड(i) और (ii)	इन खंडों को संशोधित किया जायेगा और इन्हें निम्नवत पढ़ा जाए :- “(i) फुटकर दुकानों और कार्यालयों की अनुमति मिश्रित उपयोग के लिए अधिसूचित सङ्कों से सटे प्लाटों पर केवल भूतल पर और अधिकतम अनुमेय भू-तल करवरेज तक के लिए दी जाएगी। ” (ii) इन सङ्कों पर बैसमेंट में चल रहा मिश्रित उपयोग भवन उपविधि के संबंधित उपलब्धों, संरचनात्मक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा अनापातिक लैंशटों के अनुसार जारी रह सकता है। तथापि, यदि बैसमेंट के ऐसे प्रयोग से प्लाट का एक ए आर अनुमेय एफ ए आर से अधिक होगा तो वह बढ़ा हुआ एफ ए आर प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों का भुगतान करना होगा। पैरा 15.3.2.1, 15.3.2.2, 15.3.2.3, 15.3.3(i) और 15.4 तथा कोई अन्य संबंधित प्रावधानों को उपर्युक्त प्रावधानों के साथ पढ़ा जायेगा। ”
15.	116	उप पैरा 15.6.3	इस उप पैरा के प्रारंभिक वाक्य को संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नवत पढ़ा जाए:- “निम्नलिखित निर्दिष्ट 24 घरों/गतिविधियों से संबंधित /व्यापार भूखण्ड में रिहायशी ईकाइयों की अधिकतम अनुमेय संख्या अथवा 4 संख्या, जो भी कम हो, तक प्रतिबंधित अधिकतम 20 वर्ग मी० क्षेत्र की प्रत्येक छोटी दुकान को ए और बी

			श्रेणी की कालोनियों को छोड़कर रिहायशी भूखण्ड में भूतल पर ही अनुमति दी जाती है। तथापि, 7.2.2007 को मौजूद निम्नलिखित निर्दिष्ट मर्दों/गतिविधियों से संबंधित / व्यापार भूखण्ड में रिहायशी इकाइयों की अधिकतम अनुमेय संख्या अथवा 4 संख्या , जो भी कम हो, तक प्रतिबंधित अधिकतम 20 वर्ग मी० क्षेत्र की प्रत्येक छोटी दुकान को ए और बी श्रेणी की कालोनियों को छोड़कर जारी रह सकती हैं किन्तु भविष्य में ए और बी श्रेणी की कालोनियों में रिहायशी भूखण्ड में भूतल पर 20 वर्ग मी० की केवल एक छोटी दुकान की ही अनुमति दी जाएगी। ”
16	117	उप पैरा 15.7.1 का खण्ड ख(ii)	इस खंड के उपरांत निम्न को जोड़ा जाएगा:- iii) “डे स्पेस सहित टैलनेस सेंटर/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक थिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद सेंटर/स्वास्थ्य और सौदर्यपरक थिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले सैलून और 7.2.2007 को संचालित।”
17	117	उप पैरा 15.7.1 का खण्ड (इ.)	इस खंड के उपरांत निम्न को जोड़ा जाएगा:- “7.2.2007 को मौजूद”
18	117	उप पैरा 15.7.1 का खण्ड (च)	इस खंड के उपरांत निम्न को जोड़ा जाएगा:- “(छ) 7.2.2007 को मौजूद और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 छ(1)(ख)सहित धारा 12ए के तहत पंजीकृत लाभ प्राप्त नहीं करने वाले गैर-सरकारी संगठन”।
19	117	उप पैरा 15.7.2	इस पैरा के अंत में निम्न नोट जोड़ा जाएगा:- “नोट : छ और ख श्रेणी की कालोनियों सहित 1962 से पहले नियोजित और विकसित सभी कालोनियों में, ऊब तक न्यूनतम आर औ डब्ल्यू निर्दिष्ट नहीं होती १ मी० की न्यूनतम आर औ डब्ल्यू पर छोटिंग सेंटरों/व्यूशन सेंटरों को घलाने की अनुमति भी दी जा सकती है।”
20	117	उप पैरा 15.7.2 से नीचे नोट	नोट में * निशान वाले शब्द “और फिटनेस सेंटर” हटाए जाएंगे।
21	117	उप पैरा 15.7.3	इस उप पैरा का ओपनिंग प्रेज इस प्रकार संशोधित किया जाएगा:- “उपरोक्त निर्दिष्ट सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक कार्यकलाप पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में निर्धारित सामान्य शर्तों संबंधी निम्नलिखित अतिशयित दशाओं के अध्यधीन होंगे।”

22	117	उप पैरा 15.7.3 का खंड(ii)	इस खण्ड को निम्न रूप में संशोधित किया जा सकता है:- " ii. बैंडों का 600 वर्ग मी० की शर्त पर एफएआर का अधिकातम दो तिहाई की अनुमति दी जाएगी जबकि गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम वैलनेस सेंटर समेत हे स्पेस/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र, फिटनेस प्रदान करने वाले सैलूनों और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवाओं को फर्शी क्षेत्र के 3/4 तक अनुमति दी जाएगी ।"
23	117	उप पैरा 15.7.3 का खंड(iii)	इस खण्ड में 'क्लीनिक' तथा 'और' शब्द के बीच में निम्न को जोड़ा जाएगा:- 'डे स्पेस/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले सैलून सहित वैलनेस सेंटर । '
24	117	उप पैरा 15.7.3 का खंड(iv)	इस खण्ड में 'नर्सिंग होम' और 'ऑपरेटिंग' शब्दों के बीच में निम्न को जोड़ा जाएगा:- 'डे स्पेस/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले सैलून सहित वैलनेस सेंटर । '
25	117	उप पैरा 15.7.3 का खंड (vi)	इस खण्ड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:- "पूर्व प्राथमिक विद्यालय (वाणिज्यिक सङ्कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड क्षेत्रेज तक केवल भू-तल पर ही होंगे । फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सङ्कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमति सभी तलों पर दी जाती है । इसके अलावा भवन उप-नियमों, ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकां और अन्न सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमति दी गई है । यदि भूखंड पर बेसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एक ए आर सीमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एक ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के मुगतान के अध्यधीन होगा ।"
26	117	उप पैरा 15.7.3 का खंड (vii)	यह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:- "कम्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र सहित पैरा 15.7.1(च) में उल्लिखित कोचिंग केन्द्र और ट्यूशन केन्द्रों के लिए अधिकातम 500

			<p>वर्ग मीटर नियमित कोप्र और बेसमेंट के अध्याधीन प्लाटों के आकार का अधिकतम अनुमेय फर्स्टी क्षेत्रफल अनुपात के 2/3 तक अनुमति होगी। प्लाट के आकार के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। बेसमेंट का प्रयोग मास्टर प्लान दिल्ली- 2021 के संगत उपबंद्यों के अनुसार अग्निशमन प्राधिकारी और अन्य सांविधिक निकायों तथा समय -समय पर संशोधित यूनिफार्डि विलिंग बाई लों, 1983 के अनुसार मंजूरी भिलाने के अध्याधीन होगा। यदि कम्प्यूटर कोपिंग और आवा कोपिंग गतिविधियों सहित कोपिंग केन्द्र और ट्यूशन केन्द्र हेतु बेसमेंट का प्रयोग प्लाट के अनुभव्य क्षेत्रफल अनुपात से अधिक होता है तो, ऐसे अधिक फर्स्टी क्षेत्रफल अनुपात का प्रयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभार की अवधारणी के अध्याधीन होगा। अन्य भौत्तुक कोपिंग/ट्यूशन केन्द्रों को घलाने के लिए मई 2008 के अंत तक वे कंफोर्मिंग स्थानों पर लिपट हो जाएंगे।</p> <p>केवल स्कूलों के बच्चों के लिए ट्यूशन केन्द्र का संचालन 100 वर्ग मीटर के किसी भी आवास समूह के भू-तल में या पलौट के फर्स्टी कोप्र के 50% भाग में, जो भी कम हो, अनुमत्य होगा।"</p>
27.	118	उप पैरा 15.7.3 का खंड (ix)	इस खण्ड के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए:- "(x) खंड (i) में उल्लिखित उप-पैरा 15.7.1 के अनुसार यदि गैर सरकारी संगठनों का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ तो उनका अधिसूचना की सिद्धि से 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण कराना चाहिए।" गैर सरकारी संगठनों ली गतिविधियां परिसर के केवल उस भाग से जारी रखने की अनुमति होगी जो 7.2.2007 की स्थिति के अनुसार इस शर्त के अध्याधीन अनुमति बगैर आगे बढ़ाया जाना प्रयोग में था कि यह फर्स्टी क्षेत्रफल के 3/4 से कम है।"
28	118	उप पैरा 15.8 (iv)	यह उप पैरा पढ़ने हेतु इस प्रकार संशोधित होगा:- "बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि चलाना, भवन उप-नियमों के संगत प्रावधान, ढांचागत सुरक्षा मानदंड और अग्नि सुरक्षा मंजूरी के अध्याधीन शुरूआतीय विकास में अनुमत्य होगा। यदि व्यावसायिक कार्यकलाप के लिए बेसमेंट का प्रयोग से अनुमेय हक ए आर अधिक हो जाता है तो वह हुए एक ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभार का भुगतान करने पर किया जा सकता है।"
29	118	उप पैरा 15.9 के अंतर्गत खंड(ii)	इस खंड के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए:- "वर्ष 2008-07 तथा 2007-08 के लिए नियमित प्रयोग हेतु, संपत्ति मालिक/आबंटी को खंड 15.9(v) के अंतर्गत दिनांक 30.6.2009 को

			या इससे पहले किसी भी शास्ति का भुगतान किए बागेर एक बार में पंजीकरण प्रभार तथा वार्षिक परिवर्तन प्रभार की अदायगी करना अनुमत्य होगा।"
30	118	उप पैरा 15.9 के अंतर्गत खंड(V)	इस खण्ड के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएः— "(vi) विशेष क्षेत्र में दिनांक 7.2.2007 को पहले से ही मिश्रित भूमि के अधीन आवासीय परिसर के संबंध में, भूखंडीय विकास के स्थानी/आबंटी/दखलकार से इस संबंध में एक प्रपत्र भरकर ऐसे मिश्रित उपयोग की घोषणा करके संबंधित स्थानीय निकाय को जमा करना अपेक्षित होगा और सरकार के समय-समय पर अनुमोदन से अधिसूचित दर पर दिनांक 30.6.2009 को या इससे पहले बिना कोई शास्ति दिए एक बार में पंजीकरण प्रभार और परिवर्तन प्रभार की अदायगी करनी होगी।"
31.	119	उप पैरा 15.12.1 के अंतर्गत खंड (ग)	इस खंड को पढ़ने के लिए इस प्रकार संशोधित किया जाएः— "(ग) ईएफ और जी श्रेणी की कालोनियों में, जहाँ 80 प्रतिशत आवासीय भूखंड मिश्रित उपयोग के अंतर्गत आते हों या जहाँ एक हेक्टेयर क्षेत्र में 150 दुकाने हों, स्थानीय निकाय द्वारा इस अधिसूचना की तारीख से तीन महीने के अंदर ऐसे क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाएगा।"
32	119	उप पैरा 15.12.2	इस उप पैरा के अंत में निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएः— “टिप्पणी 1: स्थानीय निकाय द्वारा शहरी गांवों तथा नियमित अनाधिकृत कालोनियों में उन क्षेत्रों/मार्गों/साइकों में इस अधिसूचना के तीन महीने के अंदर सर्वेक्षण किया जाएगा जिनका दिनांक 7.2.2007 को अधिसूचित दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के प्रावधानों के अनुसरण में सर्वेक्षण नहीं किया गया है।”
33	120	उप पैरा 15.12.3 की शर्त(iv)	इस शर्त को इस प्रकार संशोधित किया जाएः— “iv. इस खंड के अंतर्गत व्यावसायिक सड़क/क्षेत्र की अधिसूचना होने पर जैसा कि इस योजना के अध्याय 5.0 में उल्लिखित है, वे सड़कें/क्षेत्र स्थानीय शार्पिं केन्द्र माने जाएंगे इन व्यावसायिक सड़कों/क्षेत्रों पर भू-खंड स्वामियों/आबंटियों को निर्मित क्षेत्र, जो प्लाट के लिए लागू रिहायशी विकास नियंत्रण मानकों से अधिक न हो, के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर विशेष परिवर्तन प्रभारों का भुगतान करना होगा। ऐसे व्यावसायिक क्षेत्रों/साइकों में प्लाट आबंटियों/स्वामियों के लिए यह एक बार की सुविधा है और भविष्य में इसका आशय विकास नियंत्रण मानदंडों में छूट नहीं माना जाना चाहिए।”

34	120	उप पैरा 15.12.3 की शर्त (vii)	इस खंड को इस प्रकार संशोधित किया जाए:- " vii. इन सहकों पर बेसमेंट में चाल रही दुकानें भवन उपरिधि के संबंधित उपर्युक्तों, संरचनात्मक सुरक्षा और अन्वि-सुरक्षा अनापत्ति की रक्ती के अध्यधीन जारी रह सकती है। तथापि, यदि बेसमेंट के ऐसे प्रयोग से प्लाट का एकषआर अनुभेद एकषआर से अधिक होगा तो वह बढ़ दुआ एकषआर प्रयोग किया जा सकता है, जराते कि सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों का सुगतान किया जाए। "
35	122	उप पैरा 16.2(3)	इस उप पैरा को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया जाए:- " 3. विशेष क्षेत्र, अनधिकृत नियमित कालोनियों और गांव आबादी के लिए विशेष क्षेत्र भवन विनियम बनाए जाएंगे। विशेष क्षेत्र, अनधिकृत नियमित कालोनियों और गांव आबादी के सामी आगामी छ. माह के अंदर स्थानीय निकाय के पास स्वयं की पंजीकृत करवाएंगे। उनके द्वारा योग्यता प्राप्त इंजीनियर से प्राप्त संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा। 15 मीटर से अधिक ऊँची संपत्तियों के स्वामियों/दखलकारों को 30 जून 2009 तक ऊँचाई की निर्धारित स्तर तक लाना होगा। उस समय तक 15 मीटर से ऊँची संरचनाओं के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस तारीख के बाद 15 मीटर की ऊँचाई की शर्त पर इस पंजीकरण में कवर होने वाले सभी भवनों को जब तक इन क्षेत्रों के लिए विशेष क्षेत्र भवन विनियमन अधिसूचित नहीं हो जाते अथवा अधिकतम तीन वर्ष, जो भी पहले हो, दंडात्मक कार्रवाई से छूट होगी। "
36.	123	अध्याय 17 के अंतर्गत खंड 2(10)	इस खंड को इस प्रकार संशोधित किया जाए:- " सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित परिवर्तन प्रभार/अन्य शुल्क वहां देने होंगे, जहां कहाँ मास्टर प्लान/जोनल प्लान, भिन्न उपयोग विनियमों और अन्य विनियमों के अंतर्गत परिसर में भू-उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है। "
37.	126	अध्याय 17 के अंतर्गत उप खंड 8(2)(vi)	इस उप खंड को इस प्रकार संशोधित किया जाए:- "v. किसी भी उपयोग जोन में स्थित गांव आबादी (लाल डोरा/फिरनी) का भू-उपयोग रिहायशी है। "

अनुलाग्नक-ख

तालिका 5.4: विकास नियंत्रण-वाणिज्यिक केन्द्र (ग) होटल को इस प्रकार संशोधित किया जाए:-

उपयोग/उपयोग परिसर	अधिकतम क्षेत्र	एफएआर	जैचाई (मीटर)	पार्किंग मानक ईसीएस/फर्शी क्षेत्र का 100 वर्ग मीटर	अन्य नियंत्रण
(ग)होटल	40	225#	एनआर*	3@	<p>(i) प्रांगण के लिए अधिकतम 10% अतिरिक्त भू-क्षेत्र की अनुमति होगी। यदि प्रांगण के लिए अनुमति अतिरिक्त भू-क्षेत्र का उपयोग किया जाता है तो उपयोग में लाए गए भू-क्षेत्र के 25% की गणना एफएआर के लिए की जाएगी।</p> <p>(ii) तल क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) के अधिकतम 20% का उपयोग व्यावसायिक कार्यालयों, खुदरा एवं सेवा दुकानों के लिए किया जा सकता है।</p> <p>(iii) सरकार द्वारा निर्धारित/अधिसूचित किए जाने वाले प्रभारों का भुगतान करने पर ही बढ़ाए गए एफएआर की अनुमति दी जाएगी।</p>

एनआर*- कोई प्रतिबंध नहीं, एआई, दिल्ली अग्निशमन सेवा और अन्य वैधानिक निकायों से अनुमोदन की शर्त पर।

एफएआर#- एल बी जैड क्षेत्र, सिविल लाइन्स बंगला क्षेत्र तथा हेरीटेज संरचनाओं पर विधमान होटलों को छोड़कर अन्य सभी होटलों के संबंध में।

@- जिन होटलों के भवन निर्माण नवशे 27.1.2006 से पहले रवीकृत कर दिए गए हैं, उनके संबंध में 100 वर्ग मीटर फर्शी क्षेत्र अनुपात के लिए 3 ईसीएस के पार्किंग मानक केवल अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र अनुपात, जो कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में संशोधन के परिणामस्वरूप उपलब्ध कराया गया है, के लिए ही लागू होंगे। जिन होटलों के भवन निर्माण नवशे 27.1.2006 अथवा उसके बाद स्वीकृत किए गए हैं, उनके संबंध में 100 वर्ग मीटर फर्शी क्षेत्र के लिए 3 ईसीएस के पार्किंग मानक सारे भूखंड के लिए लागू होंगे।

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(DELHI DIVISION)
NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th August, 2008

S.O. 2034(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) as Public Notices vide No. S.O. 1049(E), dated 30-4-2008, 1142(E), dated 15-5-2008, 1172(E), dated 19-5-2008, 1396(E), dated 9-6-2008 and 1397(E) dated 9-6-2008 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions with regard to the proposed modifications have been considered by a Board of Enquiry and Hearing, set up by the Delhi Development Authority and also by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the modifications in the said Master Plan for Delhi, 2021 as per Annexure A and B with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

[No. K-12011/5/2007-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

Annexure-A

Sl. No.	Page No.	Para/ Clause No. of MPD- 2021	Modifications
1.	27	Condition (xvii) under sub- para 4.4.3	<p>This condition shall be substituted by the following:-</p> <p>"(xvii) Encroachment on public land shall not be regularized and shall be removed before the local body grants sanction for regularization of additional construction or height except the following:-</p> <p class="list-item-l1">(a) Projections/chajjas/ covered chajjas built up portion which existed before 7.2.2007 upto 1m above 3m height from the ground level shall be regularized for plot size upto 175 sqm on roads below 24m ROW in pre-1962 colonies (except for A & B category), in unplanned areas (including special area, village abadi and unauthorized-regularized colonies) and re-settlement colonies. The owners/occupiers shall have to obtain structural safety certificate and fire clearance within a reasonable period of time as notified by the Government. Such projections/built up portion thereon shall be counted in FAR and in case of excess FAR over and above permissible FAR, such FAR in excess shall be regularized subject to payment of appropriate charges as approved by the Government.</p> <p class="list-item-l1">(b) The local body concerned shall carry out a survey within a period of two months from the date of notification of all such projections eligible to be regularized and put such list in public domain for objections from the occupiers/owners and any person of the public against inclusion/exclusion of such projection in the list and the list thereafter will be finalized within a period of one month after considering such objections received in writing."</p>

2.	35-36	Table 5.4-4(c) Hotels	The Development Control Norms of (c) Hotels shall be substituted as per Annexure 'B'.
3.	46	Note (v) below Table 7.3	This Note shall be substituted by the following: "v. Banquet hall shall be permissible in Industrial premises subject to specifications/ regulations as may be prescribed, along with conversion charges as prescribed by the Government from time to time."
4.	46	Note (vi) below Table 7.3	This note shall be substituted by the following:- "vi. Industrial units/ plots abutting roads of 24m ROW and above shall be eligible for conversion to commercial use within the existing development control norms, subject to payment of conversion charges as prescribed by the Government from time to time, and cost of parking as decided by Government from the time to time. The activities permissible in local shopping centres will be permitted in such plots. In addition, multilevel parking shall be permissible activity. However, this shall not be permitted on non-conforming/ regularized industrial cluster. The above provision shall not affect the Supreme Court orders in any way."
5.	78	Clause (vii) below sub-para 12.12.2	This clause shall be substituted by the following:- "vii. Maximum 10 FAR permissible for non-inflammable, non-hazardous commercial activities subject to payment of conversion charges/levies, as prescribed by the Government from time to time."
6.	97	Sl.No.14 under Table 13.21	In this Sl.No. under the Heading 'Activity permitted', after Indoor Games Hall, " Swimming Pool " shall be added.
7.	97	Table 13.21,	Below this table, the following foot note shall be added:- "Note 1: Physical training with equipment is permitted activity in the Indoor Games Halls".

8.	113	Clarification on 'Other activity' under sub-para 15.3.2(1)	<p>This clarification shall be substituted by the following:</p> <p>" "Other Activity" restricted to guest houses, nursing homes and pre-primary schools, as defined in para 15.7.1, subject to conditions contained in para 15.7, in plots abutting roads of minimum 18m ROW in regular plotted development, since these activities are in the nature of 'Public and Semi Public' facilities. New banks, fitness centres, wellness centres and NGOs will not be permissible. Banks which existed as on 7.9.2006, fitness centres, wellness centres and NGOs which existed as on 7.2.2007, (as defined in para 15.7.1), in accordance with notifications issued in this regard from time to time, and are on plots abutting roads of minimum 18m ROW, on the date of notification, shall however, continue."</p>
9.	114	Clarification (4) below sub para 15.3.2 (Group Housing in all categories of colonies)	<p>This shall be substituted by the following:-</p> <p>"Only professional activity, small shops in terms of para 15.6.3 and tuition centres for school children only shall be permissible. Retail shops specifically provided for in the lay out plan of group housing and activities permitted in group housing under para 15.4(l) would be permissible."</p>
10.	114	Clause (i) under Sub-para 15.3.3	<p>This Clause shall be modified to read as under:-</p> <p>"(i) Where more than 50% of the plots in a stretch/street, are having shops/ offices and other activities permitted in Local Shopping Centres on ground floor, such streets/ stretches shall be eligible for notification as mixed use street".</p>
11.	114	Clause (iv) under Sub Para 15.3.3	<p>After this clause, the following note shall be added:-</p> <p>"Note-1</p> <p>The local body shall carry out a survey in those streets/roads in urban villages and regularized-unauthorized colonies not surveyed pursuant to the provisions of MPD-2021 notified on 7.2.2007, within a period of three months of this Notification."</p>

12.	115	In Group Housing under Sub-Para 15.4(ii)	After the sentence " Only ----permissible", the following shall be added:- "However, the entire ground floor of DDA flats on mixed use/ commercial use area/ stretches/ roads is allowed for mixed use/ commercial use. No amalgamation of two or more DDA flats shall be allowed."
13.	115	15.6	The Heading of this sub para shall be modified to read as " Retail Shops and Offices ".
14.	115	Clause (i) & (ii) under sub-para 15.6.1	These clauses shall be modified to read as under: "(i) Retail shops and Offices shall be permitted on plots abutting streets notified for mixed use only on the ground floor upto the maximum permissible ground floor coverage. (ii) Mixed use from basement on such streets may be allowed, subject to relevant provisions of building bye-laws, structural safety and fire safety clearance. However, if such use of basement leads to exceeding the permissible FAR on the plot, such FAR in excess shall be used, subject to payment of appropriate charges prescribed with the approval of Government. Paras 15.3.2.1, 15.3.2.2, 15.3.2.3, 15.3.3(i) and 15.4 and any other relevant provisions shall be read alongwith the above provisions."
15.	116	Sub Para 15.6.3	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:- "Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with the following specified 24 items/activities are allowed on ground floor only in residential plot, excluding A & B category of colonies. However, small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of dwelling units in the plot or four in number, whichever is less, trading in or dealing with specified items/

			activities existing as on 7.2.2007 may continue on ground floor only in a residential plot in A & B category of colonies but in future only one small shop of 20 sqm area shall be allowed on ground floor in a residential plot in A & B category of colonies.”
16.	117	Clause b(ii) of sub-para 15.7.1	After this Clause, the following shall be added:- “iii. Wellness Centers including Day Spas/ Weight Loss Centres/ Ayurvedic Centres offering Ayurvedic treatment/ Salons offering fitness & aesthetic medical services and operating as on 7.2.2007.”
17.	117	Clause (e) of Sub-para 15.7.1	At the end of this Clause, the following shall be added:- “as existed on 7.2.2007.”
18.	117	Clause (f) of Sub-para 15.7.1	After this Clause, the following shall be added:- “(g) Non-profit making Non-Governmental Organizations (NGOs) existing as on 7.2.2007 and registered as such under Section 12A read with Section 12AA(1)(b) of the Income Tax Act, 1961.”
19.	117	Sub Para 15.7.2	At the end of this sub para, the following note shall be added:- “Note: Coaching centres/tuition centres shall also be allowed to operate on a minimum ROW of 9m unless lesser ROW is specified, in all colonies planned and developed prior to 1962 Including A and B category colonies.”
20.	117	Notes below Sub-para 15.7.2	In the Note with * mark, the words ‘and fitness centers’ shall be deleted.
21.	117	Sub Para 15.7.3	The opening phrase of this sub-para shall be modified as under:- “The above mentioned public and semi-

			<p>public activities shall be subject to the following overriding conditions on the general conditions prescribed in preceding paras:-"</p>
22.	117	Clause (ii) of sub-para 15.7.3	<p>This Clause shall be substituted by the following:-</p> <p>"ii. Banks shall be permissible on maximum $\frac{2}{3}$rd of FAR subject to 600 sqm while guest house, nursing homes, Wellness Centers including Day Spas/ Weight Loss Centres/ Ayurvedic Centres offering Ayurvedic treatment/ Salons offering fitness & aesthetic medical services will be permissible upto $\frac{3}{4}$th of the floor area."</p>
23.	117	Clause (iii) of sub-para 15.7.3	<p>In this Clause, between the words "clinics" and "and", the following shall be inserted:-</p> <p>"Wellness Centers Including Day Spas/ Weight Loss Centres/ Ayurvedic Centers offering Ayurvedic treatment/ Salons offering fitness & aesthetic medical services".</p>
24.	117	Clause (iv) of sub-para 15.7.3	<p>In this Clause, between the words "Nursing Homes" and "operating", the following shall be inserted:-</p> <p>"Wellness Centers Including Day Spas/ Weight Loss Centres/ Ayurvedic Centres offering Ayurvedic treatment/ Salons offering fitness & aesthetic medical services."</p>
25.	117	Clause (vi) of Sub- para 15.7.3	<p>This clause shall be substituted by the following:</p> <p>"Pre-primary school (other than those on plots abutting commercial streets) shall be restricted only to the ground floor upto the permissible ground coverage.</p> <p>Fitness Centre (including Gymnasium, Yoga/Meditation Centre), (other than those on plots abutting commercial streets) is permitted on all floors. It is also permitted in the basement subject to relevant provisions of Building Bye Laws,</p>

			structural safety norms and fire safety clearance. In case the use of basement leads to exceeding the permissible FAR on the plot, such FAR in excess shall be used subject to payment of appropriate charges prescribed with the approval of Government".
26.	117	Clause (vii) of Sub Para 15.7.3	<p>This clause shall be modified to read as under:-</p> <p>"Coaching centres and tuition centres referred to in para 15.7.1 (f) including computer coaching and language coaching centres shall be permissible up to 2/3rd of the maximum permissible FAR of the plot size subject to a maximum of 500 sqm built area and basement. There shall be no restriction on the size of the plot. Use of basement shall be subject to clearance from the fire authorities and other statutory bodies as per the relevant provisions of MPD 2021 and Unified Building Bye-Laws, 1983, amended from time to time. In case the use of basement for coaching centres and tuition centres including computer coaching and language coaching activity leads to exceeding the permissible FAR on the plot, such FAR in excess shall be used subject to payment of appropriate charges prescribed with the approval of Government. Other existing coaching/tuition centres may be allowed to continue till end of May, 2008 and shift to conforming locations by then.</p> <p>The tuition centres for school children only, shall also be permissible in the ground floor dwelling of any group housing on a maximum floor area of 100 sqm or 50% of the floor area of the flat, whichever is less."</p>
27.	118	Clause (ix) of Sub-para 15.7.3	<p>After this Clause, the following Clause shall be added:-</p> <p>"(x) NGOs as referred to in Clause (g) of Sub-para 15.7.1, if not registered as yet, should get themselves registered within one year from the date of Notification. Activities of NGOs will be allowed to</p>

			<p>continue only from that part of the premises which was in use as on 7.2.2007 without permitting any further increase subject to the condition that it is less than 3/4th of the floor area.”</p>
28.	118.	Sub Para 15.8 (iv)	<p>This sub para shall be modified to read as under:-</p> <p>“Professional activity in basements is permissible in plotted development, subject to relevant provisions of Building Bye-Laws, structural safety norms and fire safety clearance. In case, the use of basement for professional activity leads to exceeding the permissible FAR on the plot, such FAR in excess shall be used subject to payment of appropriate charges prescribed with the approval of Government.”</p>
29.	118	Clause (ii) under sub-para 15.9	<p>At the end of this Clause, the following shall be added :-</p> <p>“For mixed use for the year 2006-07 and 2007-08, the property owner/allottee shall be allowed to pay one time registration charges and annual conversion charges without payment of any penalty under Clause 15.9 (v) for mixed use on or before 30.6.2009.”</p>
30.	118	Clause (v) under sub-para 15.9	<p>After this clause, the following clauses shall be added :</p> <p>“(vi) In respect of residential premises already under mixed use on 7.2.2007 in Special area, the owner/allottee/occupier of the plotted development shall be required to declare such mixed use by filling up a form in this respect and depositing it with local body concerned and pay one time registration charges and conversion charges without penalty on or before 30.6.2009 at the rate to be notified with the approval of the Government from time to time.”</p>

31.	119	Clause (c) under Sub-para 15.12.1	<p>This Clause shall be modified to read as under:-</p> <p>"(c) In E, F & G category colonies, where 80% of residential plots are under mixed use, or if there are 150 shops, within a contiguous area of 1 hectare, the Local Body shall carry out a survey in such areas within a period of three months from the date of this Notification."</p>
32.	119	Sub-para 15.12.2	<p>At the end of this sub-para, the following note shall be added:-</p> <p>"Note 1: The local body shall carry out a survey in those areas/ streets/roads in urban villages and regularized-unauthorized colonies not surveyed pursuant to the provisions of MPD-2021 notified on 7.2.2007, within a period of three months of this notification."</p>
33.	120	Condition (iv) to sub-para 15.12.3	<p>This condition shall be modified to read as under:</p> <p>"iv. On notification of a commercial street/ area under this clause, such streets/ areas shall be considered as local shopping centres as mentioned in Chapter 5 of this Plan. The plot owners/ allottees on these commercial streets/ areas shall have to pay conversion charges as prescribed by the Government from time to time, in respect of the built up area which shall not exceed the residential development control norms applicable to the plot. This is a one-time facility for plot allottees/ owners in such commercial areas/ streets and shall not be construed as relaxation of the development control norms in future."</p>
34.	120	Condition (vii) to sub-para 15.12.3	<p>This condition shall be modified to read as under:</p> <p>"vii. Commercial activity in basement on such streets shall be permitted, subject to relevant provisions of building bye laws, structural safety and fire safety clearance. However, If such use of basement leads to exceeding the permissible FAR on the plot,</p>

			such FAR in excess shall be used subject to payment of appropriate charges prescribed with the approval of Government."
35.	122	Sub-para 16.2(3)	<p>This Sub-para shall be modified to read as under:</p> <p>"3. Special Area building Regulations shall be framed for special area, unauthorized regularized colonies and village abadis. Owners in special area, unauthorized regularized colonies and village abadi shall register themselves with the Local Body within the next six months. They will also submit a certificate of structural safety by qualified engineers. Owners/ occupiers of properties beyond 15 m height, may bring the structure within prescribed height by 30th June, 2009. Till such time, no punitive action would be taken against these structures beyond 15 m height. Subsequent to this date, subject to height restriction of 15 m, all buildings covered by such registration shall be exempted from punitive action till Special Area Building Regulations for these areas are notified or maximum three years, whichever is earlier."</p>
36.	123	Clause 2(10) under Chapter 17	<p>This Clause shall be modified to read as under:-</p> <p>"Conversion charges/other levies as prescribed by the Government from time to time shall be payable wherever land use conversion is enabled at premise level by the Master Plan/Zonal Plan, Mixed Use Regulation and other Regulations."</p>
37.	126	Sub Clause 8(2)(vi) under Chapter 17	<p>This sub-clause shall be modified to read as under:-</p> <p>"(v) Land use of village Abadi (Lal Dora/firni) located in any use zone is residential."</p>

ANNEXURE - B

Table 5.4: Development Control-Commercial Centers of (c) Hotels shall be modified to read as under:

Use/use premises	Maximum Coverage (%)	FAR	Height (mts.)	Parking Standards ECS/100 sqm of floor area	Other controls
(c)Hotels	40	225#	NR*	3@	<ul style="list-style-type: none"> (i) Maximum 10% ground coverage shall be allowed for providing atrium. In case, the permissible additional ground coverage for atrium is utilized, 25% of the utilized ground coverage shall be counted towards FAR. (ii) Maximum 20% of the FAR can be used for the Commercial Offices, Retail & Service Shops. (iii) The enhanced FAR will be allowed subject to payment of charges to be prescribed/ notified by the Government.

NR*-No Restriction, subject to clearance from AAI, Delhi Fire Service and other statutory bodies.

FAR#- In respect of all hotels except those located in LBZ area, Civil Lines Bungalow Area and Hotels existing on heritage structures.

@- In respect of hotels where the building plans stand sanctioned prior to 27.1.2006, parking standard of 3 ECS for 100 sqm of floor area shall be applicable only for the additional FAR which will be availed consequent upon amendment to MPD 2021. In respect of hotels where the building plans have been sanctioned on or after 27.1.2006, the parking standard of 3 ECS for 100 sqm of floor area shall be applicable to the entire plot.